भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1697

दिनांक 15 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

महाराष्ट्र के बांधों में गाद और वाष्पीकरण से हो रही जल हानि को रोकने के लिए कदम

1697. डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में जयकवाड़ी, मजलगांव और अन्य प्रमुख बांधों में गाद जमने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या इन बांधों में वाष्पीकरण के कारण हो रही जल हानि को कम करने के लिए कोई वैज्ञानिक या तकनीकी उपाय अपनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार इन बांधों की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए गाद निकालने या तलकर्षण का कार्य कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए भविष्य की कार्य योजना क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): गाद निकालने संबंधीसं चालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित बांध मालिकों, राज्य सरकारों तथा परियोजना प्राधिकरणों पर निर्भर करती है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि जयाकवाड़ी बांध का जलाशय अवसादन सर्वेक्षण महाराष्ट्र इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एमईआरआई), नासिक द्वारा वर्ष 2014 में किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, जयाकवाड़ी बांध की सक्रिय भंडारण क्षमता में 8.24% की कमी आई है। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान मजलगांव बांध का गाद सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव किया है।

एमईआरआई द्वारा वर्ष 2022 में मंजरा तथा लोअर तरना बांधों के जलाशय अवसादन सर्वेक्षण भी किए गए थे। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, मंजरा बांध और लोअर तरना बांध की सक्रिय भंडारण क्षमताओं में क्रमशः 8.41% तथा 22% की कमी दर्ज की गई है।

मृदा एवं जल संरक्षण विभाग ने कृषि विभाग के सहयोग से जयाकवाड़ी बांध के प्रतिप्रवाह जलग्रहण क्षेत्र में जलग्रहण उपचार योजना के अंतर्गत सतत समोच्च खाइयाँ तथा कम क्षमता वाले जल भंडारण संरचनाओं जैसी पहलों को कार्यान्वित किया है।

(ख): महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि बांध में वाष्पीकरण के कारण होने वाली जल की बर्बादी को कम करने हेतु अभी तक कोई वैज्ञानिक अथवा तकनीकी उपाय नहीं अपनाए गए हैं।

(ग) और (घ): महाराष्ट्र सरकार ने पायलट आधार पर छह चयनित प्रमुख बांधों से गाद एवं रेत को हटाने पर विचार किया है तथा जयाकवाड़ी बांध को भी इस पहल में शामिल किया है। सरकार वर्तमान में अपनी गाद अवसादन नीति एवं कार्यक्रम को अद्यतन कर रही है। इन छह पायलट परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव के आधार पर गाद निकासी या ड्रेजिंग कार्यक्रम को चरणबद्ध रूप से अन्य परियोजनाओं तक विस्तारित किया जाएगा।

*****